(e) whether he sold his invention to the Railways itself?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes, Sir.

(b) There was no direct connection between the invention and the inventor's officail duties.

(c) Yes, Sir.

(d) Patent of his invention has been taken out in India, United Kingdom, West Germany, Canada, France, Czechoslovakia, Italy, United States of America, Brazil, Japan and Australia.

(e) He was granted permission to take out patent of the invention in the countries listed above at Government cost, on the condition that patent is assigned to the President. Shri Suri has assigned the patent to the President and, as a result, all rights, powers and benefits of the said invention belong to and are the exclusive property of the Government of India.

Fall in Prices of Cotton

*998. SHRI D. R. PARMAR:
SHRI R. K. AMIN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation regarding the fall in price of "Gujarat-67" cotton;

(b) whether the depression in price is mainly due to Government's policy announced much earlier for the import of cotton from foreign countries in huge quantity;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the action proposed to be taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). The prices of indigenous cottons in the current season, which had been rising, showed a declining trend from the third week of January, 1968, essentially due to seasonal factors and self-discipline by member-mills of I.C.M.F. Prices of Gujarat-67 cotton, which reflected a like trend, have picked up again. The price situation of Indian cottons is under constant review by Government and suitable measures are taken as and when necessary.

सरकारी क्षेत्र के कारखाने

*999. श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कारखानों की क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण 1966–67 में कितनी हानि हुई है; और

(ख) उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता अभी धीरे-धीरे स्थापित की जा रही है और इस अवस्था में यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि कितनी क्षमता अप्रयुक्त रही । इस सन्दर्भ में यह भी निश्चित रूप से बता सकना सम्भव नहीं है कि इससे कितनी हानि हुई है । फिर भी सरकारी क्षेत्र के कुछ

उपक्रमों में पहले से स्थापित क्षमता का इस्तेमाल करनेमें कुछ अन्तर रहा है । यही बात गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों के बारे में भी कही जा सकती है ।

(ख) सरकार क्षमता के उपयोग में इस अन्तर का पता लगाने के लिये उच्चतम स्तर पर और अधिक ध्यान दे रही है और सरकार द्वारा उपक्रमों के अध्यक्षों को हिदायतें दे दी गई हैं कि क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की योजनाएं लागू करें । उन्हें बताये गए उपाय ये हैं :—

(1) उन वस्तुओं के उत्पादन में विविधता लाना जिनकी मांग है और जिनमें ऐसे फालतू पुर्जे शामिल है जिनकी बार-बार मांग होती रहती है;

(2) सरकार के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं सम्भव हो सके उन वस्तुओं के अधिक आर्डर प्राप्त करना जिनका औद्योगिक उत्पादों की मांग पर सीधा असर पड़ता हो;

(3) निर्यात को बढ़ावा देने तथा देश के अन्दर बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से बिक्री कला को जोरों से चलाने के लिये विक्रय को सुदृढ़ करना; और

(4) विद्युत परियोजनाओं, इस्पाती ढांचे तथा भारी इंजीनियरी उद्योगों के क्षेत्र में 'टर्न की' आधार पर ठेके प्राप्त करने के लिये साथ समूह का निर्माण करना ।

Page Board for Railway Employees

*1000. SHRI M. L. SONDHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Uttariya Railway Mazdoor Union has demanded a separate wage board for the Railway employees;

(b) whether the Union has also demanded non-introduction of automation to avoid retrenchment of staff; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). No reference has been received from the Union although there have been such demands from different quarters.

(c) Railway employees are servants of the Central Government and therefore their wages are determined on the same basis as is adopted for all Central Government employees. It will not, therefore, be appropriate to have a separate wage board for Railway employees only.

As regards automation, it is the policy to introduce it where it is found to be in the public interest, having regard to the results to be achieved. However, any such introduction of automation is accompanied with certain guarantees including non-retrenchment, designed to safeguard the interests of existing employees.

कपड़े की उत्पादन लागत

*1001. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगातार कपड़ की उत्पादन लागत बढ़ रही है और उसका उत्पादन गिर रहा है;

(ख) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिलों के फैडरेशन ने धागे और कपड़े पर उत्पादन